राजस्थान में कृषि व विपणन

⇒ राजस्थान के सकल मूल्य राज्य वर्द्धन (SGVA) में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंध क्षेत्र का योगदान वर्ष 2021-22 में 30.23 प्रतिशत है।

⇒ जिसमे फसल क्षेत्र का अंश 45.94 प्रतिशत, पशु क्षेत्र का अंश 46.25 प्रतिशत, वानिकी का 7.44 प्रतिशत तथा मत्स्य क्षेत्र का 0.37 प्रतिशत हैं।

⇒ राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि के विभिन्न उपक्षेत्रो का राज्य के सकल मूल्य वर्द्धन (SGVA) में योगदान–

(1) फसल क्षेत्र →

स्थिर कीमत (2011-12) – 12.61 प्रतिशत

प्रचलित कीमत – 13.89 प्रतिशत

(2) पशुधन क्षेत्र →

स्थिर कीमत → 13.34 प्रतिशत

प्रचलित कीमत → 13.98 प्रतिशत

ACADEMY
Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Q.① राज० के कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के उपक्षेत्रो का योगदान है?

(a) फसल → 45.94 प्रतिशत

(b) पशुधन क्षेत्र → 46.25 प्रतिशत

(c) विकल्प a व b

(d) इनमें से कोई नही

Q.② राज्य के सकल मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्यो पर फसल क्षेत्र तथा पशु धन का अंशदान है?

(a) 12.61, 13.34 प्रतिशत

(b) 45.94 प्रतिशत, 46.25 प्रतिशत

(c) 46.25 प्रतिशत 7.25 प्रतिशत

(d) इनमें से कोई नही

ACADEMY

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

भूमि उपयोग ⇒

⇒ राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 में 342.90 लाख हैक्टर है जिसमे 52.58 प्रतिशत (180.32 लाख हे.) शुद्ध बोये गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

कृषि जोत →

⇒ राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतो की संख्या 76.55 लाख है जबकि 2010-11 में ये संख्या 68.88 लाख थी। अर्थात् भूमि जोतो की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

⇒ राज्य में सीमांत लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम तथा बड़े आकार की जोतो का प्रतिशत क्रमशः 40.12 %, 21.90 %, 18.50 %, 14.79 %, 4.69 % प्रतिशत है।

सीमांत → 1 हेक्ट. से कम
लघु → 1 से 2 हेक्ट.
अर्द्ध मध्यम → 2 से 4 हेक्ट.
मध्यम → 4 से 10 हेक्ट.
बड़े आकार → 10 व अधिक हेक्ट.

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

⇒ वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम आकार के जोतो में वृद्धि हुई है जबकि बड़े आकार की जोतो की संख्या में 11.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।

⇒ वर्ष 2010-11 से 2015-16 में कृषि जोतो के कुल क्षेत्रफल में 1.24 प्रतिशत की कमी हुई है।

⇒ वर्ष 2015-16 में राजस्थान में कृषि जोतो का कुल क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टयर है।

⇒ वर्ष 2015-16 (कृषि गणना अनुसार) राज्य में भूमि जोतो का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा है। जो 2010-11 की तुलना में 11.07 प्रतिशत कम है।

ACADEMY

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Topic :

Date :

Class : 32

महिला प्रचालित जोत धारक →

⇒ राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतो की संख्या 7.75 लाख है।

⇒ वर्ष 2010-11 की तुलना में महिला भूमि जोतो की संख्या में 41.94 प्रतिशत में वृद्धि हुई हैं।

⇒ वर्ष 2015-16 में महिला भूमि जोतो का क्षेत्रफल 16.55 लाख हेक्टेयर है।

⇒ 2010-11 की तुलना में इसमे 24.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ACADEMY

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

कृषि उत्पादन ⇒

⇒ वर्ष 2021-22 में खाद्यान्नो का कुल उत्पादन → 225.20 लाख मैट्रिक टन हैं।

⇒ खरीब खाद्यान्न का उत्पादन 84.90 लाख टन तथा रबी खाद्यान का उत्पादन 140.30 लाख टन होता है।

⇒ वर्ष 2021-22 में दलहन का उत्पादन 42.62 लाख मैट्रिक टन है।

⇒ 2021-22 में तिलहन का उत्पादन 92.04 लाख मैट्रिक टन है। गन्ना का उत्पादन 2.47 लाख मैट्रिक टन, कपास का उत्पादन 23.31 लाख गांठे।

⇒ कपास की 1 गांठ का वजन 170 Kg होता है।

⇒ भारत में विभिन्न फसलो में राजस्थान का योगदान →

फसल	देश में उत्पादन (%)
1. बाजरा	⇒ 45.56 प्रतिशत
2. राई व सरसो	⇒ 46.28 प्रतिशत
3. कुल तिलहन	⇒ 20.30 प्रतिशत
4. चना	⇒ 23.44 प्रतिशत
5. कुल दलहन	⇒ 19.41 प्रतिशत
6. ग्वार	⇒ 78.62 प्रतिशत

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Topic :

Date :

Class : 32

* राज० की प्रमुख फसलो में स्थिति →

फसल	राज० की स्थिति
1. बाजरा	⇒ प्रथम
2. राई व सरसो	⇒ प्रथम
3. पोषक अनाज	⇒ प्रथम
4. कुल तिलहन	⇒ प्रथम
5. कुल दलहन	⇒ प्रथम
6. चना	⇒ प्रथम
7. मूंगफली	⇒ दूसरा
8. सोयाबीन	⇒ तीसरा
9. ग्वार	⇒ प्रथम

कलाम ACADEMY

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Topic :   Date :

Class : 33.

कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाए एवं कार्यक्रम

① मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना →

⇒ शुरु → 2017-18

⇒ प्रारम्भ में ये योजना ③ कृषि जलवायु खंडो - कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में शुरु की गयी थी।

⇒ 2018-19 से ये योजना राज्य के सभी जलवायु (10) खंडो में शुरु कर दी गयी है।

⇒ किसानो को स्वयं के खेतो में अच्छे किस्म के बीज उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

② जीरो बजट नेचुरल फॉर्मिग →

⇒ वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में "खेती में जान तो सशक्त किसान" की सोच रखते हुए ये योजना ③ जिलो में (टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा) 'पायलेट प्रोजेक्ट' के रूप में शुरु किया गया था।

⇒ वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसे राज्य के ⑮ जिलो में लागू कर दिया गया है।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ⇒

⇒ वर्ष 2007-08 में यह मिशन राज्य में गेहूँ व दलहन में प्रारम्भ किया गया था।

⇒ इसमें केन्द्र व राज्य का अनुपात (अंश) 60 : 40 है।

⇒ वर्तमान में इस मिशन को मोटे अनाजों में भी शुरू कर दिया गया है।

मक्का → 5 जिले
जौ → 7 जिले
ज्वार → 10 जिले

(4) राष्ट्रीय टीकाऊ खेती मिशन-2014-15

⇒ ये योजना पूर्व में संचालित योजनाओ →
राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता परियोजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सम्मिलित करके शुरू की गयी।

⇒ राष्ट्रीय टीकाऊ खेती मिशन में केन्द्र व राज्य का अंश 60 : 40 है।

⇒ राष्ट्रीय टीकाऊ मिशन में निम्न (4) सब-मिशन सम्मिलित किये गए है।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

1. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
2. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड
3. परम्परागत कृषि विकास योजना
4. कृषि वानिकी पर उपमिशन

⇒ परम्परागत कृषि विकास योजना ⇒ इस मिशन का उद्देश्य रसायनो व कीट नाशको का प्रयोग कम करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना है।

(5) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ⇒

⇒ वर्ष 2007-08 में शुरु की गयी इस योजना में केन्द्र व राज्य का अंश 60 : 40 है।

⇒ इस योजना का उद्देश्य कृषि व संबंधित क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।

ACADEMY
Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

(6) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना →

⇒ खरीफ 2016 से शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत कृषि फसलो का बीमा शुरू किया गया।

⇒ बीमा की प्रीमियम राशि जो किसान द्वारा दी जाएगी वह खरीफ फसलो के लिए (2) प्रतिशत, रबी फसलो के लिए (1.5) प्रतिशत, वाणिज्यक बागवानी (5) प्रतिशत है।

⇒ भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्रो के लिए (30) प्रतिशत सिंचित क्षेत्रो के लिए (25) प्रतिशत अधिकतम प्रीमीयम का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) राष्ट्रीय बागवानी मिशन →

⇒ यह मिशन वर्ष 2005-06 में राज्य के चयनित (24) जिलो में शुरू किया गया था।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

कृषि विपणन →

→ कृषि विपणन के अंतर्गत फसल उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुचने के दौरान जितनी क्रियाए की जाती है।

जैसे → उत्पादन, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, परिवहन, भण्डारण, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार आदि। को विपणन कहा जाता है।

→ कृषि कार्यो के दौरान दुर्घटना से किसानो खेतीहर मजदूरो व हमालो को सहायता देने के लिए 'राजीव गांधी कृषक साथी योजना' शुरु की गयी।

→ राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के अलावा किसानो को गुणवता पूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने हेतू वर्ष 2014 में 'किसान कलेवा योजना' शुरु की गयी।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

⇒ महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना-2015

⇒ इस योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता, विवाह के लिए सहायता, मेधावी छात्र पुरस्कार, चिकित्सा सहायता, पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है।

⇒ प्रसूति सहायता महिला अनुज्ञप्ति-धारी श्रमिक को 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य दी जाएगी।

⇒ अनुज्ञप्ति-धारी महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह पर 50 हजार की सहायता तथा पुत्रीयो के विवाह की सहायता के लिए 50 हजार रु. दी जायेगी।

⇒ यह सहायता अधिकतम ② पुत्रियो के लिए है।

⇒ पुरुष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य पितृत्व सहायता दी जाएगी।

ACADEMY

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Topic :

Date :

Class : 33.

कृषि विपणन बोर्ड →

⇒ देश में कृषि उपज मंडीयो की स्थापना, विस्तार तथा कार्य पर नियंत्रण हेतू कृषि विपणन बोर्ड स्थापित किए गए।

⇒ राज० राज्य में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 17 जून 1974 को जयपुर में की गयी।

⇒ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 25 सदस्य होते है उनमें से 10 सदस्य मंडी समितियो अध्यक्ष में से होते है।

⇒ कृषि विपणन बोर्ड अपनी वित्तीय साधनो की पूर्ति मंडी समितियो से ~~अपनी~~ उनकी आय का एक निश्चित प्रतिशत लेकर कर देता है।

⇒ सुपर A श्रेणी की मंडी से 30 प्रतिशत, A श्रेणी की मंडी से 20 प्रतिशत एवं B श्रेणी की मंडी से 10 प्रतिशत लेता है।

⇒ C व D श्रेणी की मंडीयो से कृषि विपणन बोर्ड उसकी आय का कोई हिस्सा नही लेता।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Topic :

Date :

Class : 33

कृषि विपणन बोर्ड के कार्य →

① कृषि मंडी कर्मचारियो का प्रशिक्षण, श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण की सुविधाओ का विकास।

⇒ मंडी क्षेत्रो में सड़को का निर्माण मंडी-यार्ड, सब-यार्ड का विकास करना।

एवं बोर्ड कार्यालय का रखरखाव करना।

② आवश्यकता होने पर मंडी समितियो को कार्य सम्पादन करने कृषि विपणन मे सुधार हेतू राज्य सरकार को सलाह देना।

③ मंडी समितियो के कार्य संचालन हेतू उपनियम बनाना तथा मंडीयो के कार्य की देखभाल करना।

ACADEMY

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Topic :

Date :

Class : 33.

कौसांब (COSAMB) → Council of state Agricultural Marketing Board)

⇒ इसकी स्थापना राज्य कृषि विपणन बोर्डो की शीर्ष संस्था के रूप में फरवरी 1988 में की गयी।

⇒ इसका मुख्य कार्य कृषि विपणन बोर्डो में समन्वय स्थापित करना है।

सहकारी कृषि विपणन →

⇒ राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)
(नाफेड - नेशनल एग्रीकल्चर कोपेरिव मार्केटिंग फेडरेशन (NAFED)

⇒ राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संघो ने मिलकर अक्टुम्बर 1958 में नाफेड की स्थापना की।

⇒ जिसका मुख्य कार्यालय ⇒ दिल्ली

नाफेड के कार्य →

① अन्तर्प्रदेशीय व्यापार को प्रोत्साहित करना।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

② विदेशी कृषि व्यापार को प्रोत्साहित करना।

③ नाफेड सरकार के लिए तिलहन, दलहन, एवं मोटे अनाज को MSP कीमतो पर क्रय करना।

④ कृषि उत्पादो के परिष्करण का कार्य करना।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम → (NCDC)

⇒ इसकी स्थापना 1963 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत सहकारी सिद्धान्तो के आधार पर की गयी।

⇒ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि उत्पादो के सहकारी विपणन परिष्करण एवं संग्रहण कार्य के आर्थिक क्षमता से करने समितियाँ स्थापित करने में सहयोग करते है।

ACADEMY
Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

जनजाति -उत्पाद सहकारी विपणन संघ → (TRIFED)

⇒ इसकी स्थापना 1987 में जनजाति क्षेत्रो में उत्पादित उत्पादो एवं हस्तकला उत्पादो के विपणन एवं विकास की संस्था है।

⇒

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF)

⇒ इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गयी।

⇒ उपभोक्ता सहकारी आंदोलन के प्रमुख संचालन का कार्य करना।

राजफेड (RAJFED)

⇒ इसकी स्थापना 26 नवम्बर 1957 को की गयी।

⇒ बाजार में कृषि उत्पादो की खुली नीलामी विधि में भाग लेकर उत्पादो का क्रय करना।

⇒ उत्पादन के विभिन्न साधनो जैसे - उर्वरक, कृषि यंत्र उन्नत बीज कीटनाशी दवाइयाँ जिप्सम आदि की पूर्ति किसानो को करना।

⇒ पशुओ के लिए दाना निर्मित करने का कारखाना स्थापित करना।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Topic :
Date :
Class : 34

तिलम संघ →

⇒ राज० राज्य में राज्यस्तरीय तिलहन उत्पादको के सहकारी संघ को तिलम संघ कहते है।

⇒ इसकी स्थापना जुलाई 1990 में की गयी।

मानक

ISI →

⇒ 1 अप्रैल 1987 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गयी।

⇒ इस ब्यूरो द्वारा ही विभिन्न उत्पादो पर जैसे- इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, रसायन आदि उत्पादो पर ISI मानक लगाया जाता है।

ECO-MARK →

⇒ ये मार्क भारत सरकार कें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फरवरी 1991 से पर्यावरण मित्र उत्पादो पर लगाया जाता है।

चिन्ह →

Kalam ACADEMY

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Topic :   Date :

Class : 34

F. P. O. MARK → (Fruits Products Order)

⇒ यह मार्क फल व सब्जियो के परिष्कृत उत्पादो पर लगाया जाता है।

जैसे → आचार, मुरब्बा, जूस आदि।

शाकाहारी व मांसाहारी उत्पादो पर चिन्ह →

⇒ 20 जून 2002 से खाद्य पदार्थो के प्रत्येक पैकेट पर मांसाहारी अथवा शाकाहारी होने से संबंधित यह चिन्ह लगाना अनिवार्य कर दिया है।

चिन्ह → ▣ शाकाहारी उत्पादो के लिए हरा तथा

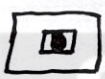

▣ मांसाहारी के लिए महरून कलर होता है।

⇒ यह चिन्ह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006

⇒ इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य से संबंधित विभिन्न अधिनियमो को सम्मिलित करते हुए एक कानून बनाना है।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Q.① अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था (ISO) की स्थापना कब हुई ?

(a) 25 फरवरी 1947

(b) 2 जनवरी 1968

(c) 28 अप्रैल 1965

(d) इनमें से कोई नही

⇒ यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादो के मानकीकरण कर उनके विनिमय को बढ़ाने का कार्य करती है।

Q.② राज॰ कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति - 2019 कब जारी की गयी ?

Ans. 17 दिसम्बर 2019

⇒ इस नीति का उद्देश्य समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियो को कम करना।

⇒ तथा कृषको एवं उनके संगठनो की सहभागिता बढ़ाना।

⇒ राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलो जैसे जीरा, धनिया, मैथी, सौंप, अजवायन, ईसबगोल, पलहन, तिलहन, मेंहदी, किन्नू, अनार एवं ताजा सब्जीयो आदि के मूल्य संवर्द्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

Topic :

Date :

Class : 34

Q.① कृषक कल्याण कोष जिसका गठन 16 दिसम्बर 2019 को किया गया। ये कोष कितने रुपये का गठित किया गया है?

Ans. 1 हजार करोड़ रुपये

→ इस कोष के लिए बैंको से कुल 2 हजार करोड़ रु. का ऋण लिया जा चुका है।

कलाम ACADEMY

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.